मान्यवर आर. पी. सेठी और एस. एस. सुधलकर, न्यायाधीशों के सामने।

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और अन्य,—**अपीलकर्ता।**

बनाम

निताशा पॉल और अन्य,—**प्रतिस्पर्धी।**

एल.पी.ए. संख्या 212/1994।

23 फरवरी, 1995।

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कैलेंडर 1986—भारतीय संविधान, 1950—धारा 14 और 21—प्रवास—प्रवास द्वारा प्रवेश।

प्रार्थी के लिए: श्री आशोक अग्रवाल, वरिष्ठ प्रतिवादी वकील, श्री विक्रम शर्मा, वकील के साथ। प्रतिस्पर्धी संख्या 2 के लिए: श्री अरुण नेहरा, अतिरिक्त सहायक सरकारी वकील। प्रतिस्पर्धी संख्या 4 के लिए: श्री के.के. गुप्ता, वकील। प्रतिस्पर्धी संख्या 8 के लिए: श्री जे.एस. ठिंड, वकील।

निर्णय

1. आर.पी. सेठी, न्यायाधीश - उत्तरदाता संख्या 4 से 11 की प्रवास, यानी मिसेज पुनीत, मिसेज बिंदु बंसल, श्री सुमीत मलिक, मिसेज मोनिका भसीन, मिसेज पूजा बत्रा, श्री मनोज मित्तल, श्री तरुण कुमार भुतानी और श्री मुनिश मदान का सिविल रिट पेटीशन संख्या 13507/1993 में, जो एल.पी.ए. संख्या 212/1994 का विषय है, उसे मुख्य रूप से विदेशी परिस्थितियों पर आधारित और अनुसार नहीं होने वाले प्रावधानों और विनियमों/निर्देशों के खिलाफ चुनौती देने का विरोध करते हुए चुनौती दी गई थी - यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किए गए और इसके बाद पेटीशनर निताशा पॉल को प्रोफेशनल बी.डी.एस. के 2 वर्ष में प्रवेश के लिए और उन्होंने मेरिट में उच्च होने के अलावा पूरी रूप से प्रवास के लिए पात्र होने का दावा किया। पेटीशन को स्वीकृति दी गई थी और उचित अधिकारियों को उक्त पेटीशन के प्रवास की अनुमति देने के लिए निर्देश दिया गया कि वे तत्काल रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और सरकारी डेंटल कॉलेज, रोहतक में किसी भी प्रवास को रद्द किए बिना उक्त पेटीशनर का प्रवास स्वीकृत करें। जो उक्त रिट पेटीशन के विषय था। अन्य सिविल रिट पेटीशन जो एल.पी.ए. संख्या 78, 79, 80 और 211/1994 के विषय हैं, महसूस किया गया कि पेटीशनरों की संख्या के अनुसार इतनी सीटें बनाना संभव नहीं था और एकमात्र उपाय यह था कि उत्तरदाता प्राधिकृती - प्राधिकृतियों को उनकी प्रथम वर्ष के पेशेवर पाठ्यक्रम में उनकी प्रतिष्ठा के आधार पर मामला देखने और केवल पाँच छात्रों को, अर्थात् तीन को डेंटल कॉलेज, रोहतक और दो को डी.ए.वी. सेंटेनरी डेंटल कॉलेज, यमुनानगर में प्रवेश देने का एकमात्र रास्ता था। उत्तरदाता को आगे कहा गया कि पेटीशनरों की मेरिट सूची तैयार करें और यदि वे पाँच उपलब्ध सीटों के अंदर आते हैं, तो उन्हें उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार रोहतक और यमुनानगर में क्रमशः प्रवासित किया जाएगा। इसके अलावा यह घोषित किया गया था कि "जो कोई भी ऐसा रिट पेटीशन आएगा, वह लैट्चेस और विलंब के कारण पर आधारित होकर स्वीकृत नहीं किया जाएगा।"

2. 1993 की सिविल रिट पेटीशन संख्या 16067 में एक याचिका की गई है जिसमें विशेषज्ञों के प्रवास को रोहतक के सरकारी डेंटल कॉलेज में निरस्त करने के लिए यहां उपरोक्त नामित व्यक्तियों का जिक्र है, जो यथासूची में हैं, ताकि प्रार्थी जो अनुस्तुत मेरिट के क्रम में उच्च होने का दावा करती थी, उनकी प्राथमिकता में रौतक के सरकारी डेंटल कॉलेज में प्रवास को रद्द करने के लिए। इसके अलावा, तत्काल पेटीशनर्स को प्रवास के रूप में 2 वर्षीय पेशेवर बी.डी.एस. कोर्स में तत्काल प्रवेश के लिए एक और याचिका की गई है। इस पेटीशन की सुनवाई के लिए इसे एल.पी.ए. संख्या 78/1994 के साथ सुनवाई के लिए निर्देशित किया गया था।

3. सिविल रिट पेटीशन संख्या 8097, 8215, 8589, 9620, 7991 और 8007/1994 में, निजी प्रतिस्पर्धियों, अर्थात् भवाना नरुला, श्री मनीष जैन, मिस अंजली हुड्डा, मिस अनामिका बिश्नोई का प्रवास मुख्यतः भेदभाव और आधिकारिक उत्तरदाताओं द्वारा

अपनाई गई चयन नीति के आधार पर चुनौती करती है, और यह याचिका की गई थी कि निजी प्रतिस्पर्धियों का प्रवेश रद्द किया जाए और उत्तरदाता - प्राधिकृतियों को पेटीशनरों को प्रवेश प्रदान करने के लिए इस महकमे के दिशानिर्देशों का पालन करके पेशेवर एमबीबीएस कोर्स के 2 वर्ष में प्रवेश करने के लिए निर्देशित किया जाए, जो कि 3.6.1994 को निर्धारित किया गया था, सिविल रिट पेटीशन संख्या 5934/1992, रिचे सूद बनाम डायरेक्टर/प्रमुख, मेडिकल कॉलेज, रोहतक।

4. सभी रिट पेटीशन्स और एपील्स में, एक समान कानूनी बिंदु शामिल है जिसे समझाने और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के संबंधित प्रावधानों के व्याख्यान और सीमा की आवश्यकता की आवश्यकता है, जो बी.डी.एस. और एम.बी.बी.एस. कोर्सेज में प्रवास द्वारा प्रवेश को नियंत्रित करते हैं। इसलिए सभी एल.पी.एस. और सी.डब्ल्यू.पीएस. को एक सामान्य निर्णय के माध्यम से निपटाया जा रहा है।

5. पक्षों के बीच विवाद की दर्शनीयता और परिधि को समझने के लिए, उक्त विवाद से संबंधित वाक्यांशों में से रिट पेटीशनर निताशा पॉल के मामले के तथ्यों का विवरण किया गया है, जो बी.डी.एस. को प्रवास के प्रति संबंधित हैं। उस मामले की पेटीशनर ने एच.एल.ई.एस. डेंटल कॉलेज और हॉस्पिटल, बेलगाम (कर्नाटका) में प्रवेश प्राप्त किया था, जिन्होंने बी.डी.एस. के पहले वर्ष को पास करने के बाद डेंटल कॉलेज, रोहतक में 2वें वर्ष के लिए प्रवास के लिए आवेदन किया। यह दावा किया गया था कि डेंटल कॉलेज, बेलगाम एक मान्यता प्राप्त संस्थान था और कि उसको उसके 10+2 अंकों के आधार पर प्रवेश दिया गया था। अपने आवेदन के साथ, पेटीशनर ने कर्णाटक विश्वविद्यालय से प्राप्त अंकपत्र, हरियाणा का उसका स्थान-निवास प्रमाणपत्र और बेलगाम के डेंटल कॉलेज और हॉस्पिटल के प्रमुख डॉ से प्रमाणित करने के लिए संलग्न किया था। आरूटी के मुताबिक, अपीलकर्ता विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न कॉलेजों से पूरे देश में प्रवास की आवश्यकता है, जिसमें से केवल 49 आवेदन प्राप्त हुए थे। कहा गया है कि एक उप समिति गठित की गई थी जिसमें कॉलेज के डीन, डॉ.(मिसेज) एम.के. चढ़ा, डॉ. बी.आर. अरोड़ा और डॉ. वी.के. ग्रोवर शामिल थे, जिन्होंने केवल 23 उम्मीदवारों को पाते हैं। उपरोक्त समिति ने मेरिट के क्रम में निम्नलिखित प्रतिस्पर्धियों को रोहतक के डेंटल कॉलेज के प्रवास के लिए सिफारिश की।

1. अराधना मिश्रा,
2. उमंद एस। नैय्यर,
3. निताशा पॉल,
4. नवीन छाबड़ा,
5. पुनित,
6. पुनीत बत्रा,
7. राशि मजीठिया.

6. इसमें विवाद नहीं है कि कुल में आठ सीटें थीं और क्योंकि तीन महीने की अवधि समाप्त होने से पहले ही एक उम्मीदवार को पहले ही रोहतक के डेंटल कॉलेज में प्रवेश मिल गया था, इसलिए केवल सात उम्मीदवारों के नाम सिफारिश किए गए थे। यह मूल्यवान है कि एपेलेंट विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष ने 20.2.1991 को प्रवास के लिए मानक निर्धारित करने के लिए एक समिति की थी। जो आठवीं उम्मीदवार था जिसने निर्धारित तीन महीने की अवधि से पहले ही प्रवास किया गया था, वह उत्तरदाता मुनिश मदान था। इसका आरोप था कि उप समिति की सिफारिशों को अनदेखा किया गया और रिट पेटीशन की विवादित आदेश दिनांक 19.10.1993 के आदेश के माध्यम से प्राइवेट उत्तरदाताओं को उत्तरित सात सीटों के लिए प्रवास प्रदान किया गया। इस तरह, उत्तरदाता मुनिश मदान की सीट को बाहर रखकर। यह और भी दावा किया गया था कि हालांकि उप समिति ने पूजा बत्रा, उत्तरदाता, को अयोग्य घोषित किया था, फिर भी उसे विवादित आदेश के माध्यम से प्रवास की अनुमति दी गई थी।

7. रिट याचिकाकर्ता के दावे का विरोध इस आधार पर किया गया कि निजी का प्रवासन उत्तरदाताओं ने 1992 के सीडब्ल्यूपी नंबर 5954 में इस न्यायालय के फैसले के अनुसार निर्णय लिया था 3.6.1992, इसे रिट याचिका के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती। यह तर्क दिया गया कि जैसे प्रवास था नहीं ए कानूनी सही, याचिकाकर्ताओं सकना नहीं आह्वान क्षेत्राधिकार का यह अदालत को इसकी वैधता निर्धारित करें और परिणामस्वरूप रिट याचिकाकर्ताओं को राहत दें। यह आगे था तर्क दिया कि अध्यादेश में निर्धारित किसी भी नियम या विनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है मेडिकल/डेंटल कॉलेज, रोहतक में प्रवास। प्रवास चाहने वाले कारणों की वैधता हो सकती है द्वारा निर्णय लिया गया प्रतिवादी-विश्वविद्यालय और

उसकी राय नहीं हो सकी होना प्रतिस्थापित. प्रवासन था निजी उत्तरदाताओं को उनके व्यक्तिगत मामलों पर विचार करने के बाद और के आलोक में प्रदान किया गया इस न्यायालय द्वारा पहले दिया गया निर्णय। सभी रिट याचिकाओं में जहां याचिकाकर्ता ने मांग की है प्रवास में बीडीएस, मैदान के लिए चाह रहा है प्रवास थे समान।

8.अभी तक के रूप में का दावा याचिकाकर्ता मांग रहे हैं एमबीबीएस में स्थानांतरण का संबंध है दलीलें हैं लगभग समान। सभी रिट याचिकाकर्ताओं थे स्वीकार किया को गुज़रना एमबीबीएस अवधि पर विभिन्न कालेजोंमें देश। ऐसे तमाम कॉलेज हैं होने का दावा किया द्वारा मान्यता प्राप्त है भारतीय चिकित्सा परिषद और हैं से संबद्ध विश्वविद्यालय. याचिकाकर्ताओं के पास है उनका सफाया कर दिया 1 वर्ष व्यावसायिक पाठ्यक्रम और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में प्रवेश के लिए आवश्यक शर्तों के साथ आवेदन किया था दस्तावेज़. उन्होंने प्रतिवादी के विश्वविद्यालय कैलेंडर के आधार पर प्रवेश का दावा किया है - विश्वविद्यालय और जमा करना वह निजी उत्तरदाताओं कौन था माइग्रेट किया गया थे जिनके पास कम

निशान बजाय रिट याचिकाकर्ताओं में प्रथम वर्ष पेशेवर इंतिहान। कार्रवाई का उत्तरदाताओं का आरोप है होना इसके विपरीत तक नियम और उल्लंघन का के प्रावधानों अनुच्छेद 14 का संविधान। निजी उत्तरदाताओं का स्थानांतरण पिक एंड चूज़ के आधार पर होने का आरोप है तरीका द्वारा कौन योग्यता है कहा को पास होना गया पूरी तरह अवहेलना करना।

9.सभी में याचिकाएं आपत्तियां हैं समान पर उठाया गया मैदान वैसे ही थे जैसे थे जबकि उठाया स्वीकार बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवासन के लिए निजी उत्तरदाताओं का दावा। इसके लिए प्रस्तुत है का विचार प्रवास, कुलपति की विश्वविद्यालय ने गठित किया था अगले समिति;

1. प्रो रवि प्रकाश, सिर, विभाग का बायो-एससी., एमडी विश्वविद्यालय, रोहतक.
2. प्रो आर. के . टुटेजा, सिर विभाग का सांख्यिकी, एमडी विश्वविद्यालय, रोहतक;
3. डॉ। एसबी सिवाच, प्रो & सिर।, विभाग का दवा, चिकित्सा कॉलेज, रोहतक; और
4. सहायक रजिस्ट्रार (आर एंड एस), एमडी विश्वविद्यालय, रोहतक.

ऐसा कहा जाता है कि उपरोक्त समिति ने सभी के आवेदनों की जांच करने के बाद 3.6.1994 को बैठक की थी। जिन उम्मीदवारों ने प्रवासन के लिए आवेदन किया था, उन्होंने निम्नलिखित उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की प्रवास;

A. चिकित्सा कॉलेज, रोहतक.

1. अमित नागपाल,
2. पूजा गुलाटी,
3. विपेंडर सभरवाल,
4. एमएस। भावना नरूला और
5. मनीष जैन.

B. महाराजा अग्रसेन चिकित्सा कॉलेज, रोहतक.

1. अंजलि हूडा और
2. अनामिका बिश्नोई.

कमेटी ने यह नाम प्रस्तुत करने के लिए कारणों को व्रित्ति में निर्दिष्ट किया गया था। इसमें दावा किया गया था कि प्रवेश की अनुमति नहीं देने के बावजूद पेटीशनरों का विचार है कि उन्हें प्रवास के लिए अनदेखा किया गया है, हालांकि उनके पास अधिक प्रतिशत के अंक हैं, यह कानून की दृष्टि से समर्थनयोग्य नहीं था। उत्तरदाताओं की क्रिया का दावा किया गया है कि यह कानूनी, वैध और कानून के अनुसार है। इस संबंध में इस महकमे के निर्णयों पर भरोसा किया जा रहा है:

1. सीडब्ल्यू.पी. 9934/1993, शारधा जैन बनाम डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज, रोहतक, जिसे 26.8.1992 को निर्धारित किया गया था।

2. सीडब्ल्यू.पी. नंबर 7371/1992, संदीप गुप्ता बनाम डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज, रोहतक और जिसे 26.8.1992 को निर्धारित किया गया था।

3. सीडब्ल्यू.पी. नंबर 10527/1992, आनंद भयाना बनाम डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज, रोहतक, जिसे 26.8.1992 को निर्धारित किया गया था।

जिसमें यह ठीक किया गया था कि प्रवास एक कानूनी अधिकार नहीं होने के कारण, राइट पेटीशन्स धारित नहीं थे। यह यहां दावा किया गया है कि कोई भी पेटीशनर का कानूनी या मौलिक अधिकार उल्लंघन नहीं हुआ है, इसलिए यहां दावा किया जाता है कि इन राइट पेटीशन्स को खारिज किया जाना उचित है।

10. राइट पेटीशनर्स का दावा कि प्रवास के माध्यम से प्रवेश का विरोध किया जा रहा है, इसका प्रमुख बहाना यह है कि प्रवास एक मौलिक अधिकार नहीं है, कोई व्यक्ति न्यायालय के पास प्रवास के द्वारा प्रवेश के लिए राहत का अनुरोध कर सकता है। इसमें शारधा जैन के मामले (उपरोक्त), संदीप गुप्ता के मामले (उपरोक्त) और आनंद भयाना के मामले (उपरोक्त) पर भरोसा किया गया है। बिना शक के है कि प्रवास के माध्यम से प्रवेश का दावा नागरिक का न के एक मौलिक अधिकार ना कानूनी हक है। हालांकि, यह भी सत्य है कि यदि प्रवास के माध्यम से प्रवेश का प्रदान करने वाले उत्तरदाताओं की क्रिया को कानून द्वारा पहचानी गई किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त विचारों द्वारा प्रेरित होने के संदर्भ में, यह चुनौती कोर्ट द्वारा मुकर्रर की जा सकती है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत और मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए उचित मार्गदर्शन देने के लिए। यह अब कानून की स्थिति है कि कानून का नियम हमारे देश में अधिरक्षित है जिसे संविधान ने गारंटी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 'रेशनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टर बनाम कॉर्पोरेशन ऑफ कैलकटा' मामले में, एयर 1960 सुप्रीम कोर्ट 1355 में यह निर्णय किया कि हमारे संविधान द्वारा भाग - III में शामिल धाराओं के कारण और उसके अन्य भागों में अन्य धाराओं के कारण, हमारे संविधान में कानून का नियम गारंटीत किया गया है। राज्य को नागरिकों की तरह, उसके सभी नागरिकों को भी, भूमि के कानूनों से बाधित किया जाता था। अदालतों को सामान्य निर्माण के सिद्धांतों का पालन करना होता है कि कोई भी व्यक्ति कानून के प्रावधानों से मुक्त नहीं किया जाता है, यहां तक कि स्टैच्यूट ने मुक्ति गारंटीत करता है या मुक्ति आवश्यक अनुमान से उत्पन्न होती है। एक राज्य जिसमें लिखित संविधान है और जहां सरकार का ढांचा लोकतांत्रिक है, जैसा कि हमारे देश में है, उसका एक खड़ा विशेषता है कानून की परमाधिकारी स्थिति, जिसे सामान्यतः कानून के परम स्थान के रूप में जाना जाता है। 'कानून की प्रमाधिकारी' शब्द संक्षेप में कानून की अनिवार्य श्रेणी को सूचित करता है और इसमें ऐसी स्थिति की योजना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति कानून का आदर करता है और कानून को प्रत्येक व्यक्ति को सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से अनुसरण करना होता है। कानून की प्रमाधिकारी का उदाहरण व्यापकता है और इसे एक ऐसी स्थिति का सुझाव करता है जिसमें हर कोई व्यक्ति स्वतंत्र लोकतांत्रिक राज्य के नागरिक होते हुए भी उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कानून का पालन किया जाना चाहिए और यह किसी भी व्यक्ति, चाहे वह राज्य हो या व्यक्ति, द्वारा उल्लंघन किया नहीं जा सकता है। यदि नियमों के उल्लंघन को रोका नहीं जाता है, तो परिणाम अपर्याप्त होने की संभावना है क्योंकि लोकतांत्रिक तंत्र का बहुत रंग है कि इसे नष्ट होने की आशंका है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर मोहम्मद रशीद अहमद बनाम राज्य ऑफ यूपी, एयर 1979 सुप्रीम कोर्ट 592 और ए.के. करीपक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, एयर 1970 सुप्रीम कोर्ट 150 में कहा है: "संविधान के तहत, प्रशासन के सभी क्षेत्र में कानून की प्रमाधिकारी नियमित और नियंत्रित होती है। हमारे देश जैसे एक कल्याण राज्य में, यह अपरिहार्य है कि प्रशासन के तंत्र का क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। कानून की प्रमाधिकारी की अवश्यकता यह है कि राज्य के यंत्रणाएँ उनके कार्य को न्यायपूर्ण और न्यायसंगत रूप में निष्पादित करने का कर्तव्य हैं। सारांश में न्यायपूर्ण रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता निर्धारित करने की एक आवश्यकता जिसे कि अनुसंधान करना नहीं है, यह उन उपायों का अंग्रेजी में कहा जाता है जो न्यायिक शक्ति का प्रयास करते हैं, सिर्फ वे उपाय हैं जो न्यायपूर्ण और न्यायसंगत निर्णय को सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं, या उन्हें यदि नहीं तो एक याचिका और न्यायिक परिचय के लिए सीधे कानूनी निर्णय की व्यापकता करते हैं। हाल के वर्षों में, क्वासी-न्यायिक शक्ति का अवधारण एक कठिन से परिवर्तन का सामना कर रहा है। वह क्या कुछ साल पहले एक प्रशासनिक शक्ति के रूप में विचारित किया गया था, वह अब क्वासी-न्यायिक शक्ति के रूप में विचारित किया जा रहा है।

9. "इस बार और कहा गया था:

"यह सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक और क्वासी-न्यायिक जाँचों के संदर्भ में न्यायिक न्याय के मौलिक अवधारण का ध्यान खींचा और कहा कि कोई भी निर्णय, चाहे वह कार्यकारी, प्रशासनिक, या न्यायिक या क्वासी-न्यायिक क्यों ना हो, यदि यह निर्णय नहीं है, तो यह 'न्यायिक' नहीं हो सकता है, अर्थात एक उदार और विषयस्क मूल्यांकन है, एक मामूल और विवेचनात्मक रूप से मामूल्यांकन है, एक मामूल

और विषयस्क रूप से मामूल्यांकन है कि मामूल्यांकन होता है, जिसके बाद सुनिश्चित किया जाता है कि जो व्यक्ति के पक्ष के सुनने के बाद मामूल्यांकन होता है।"

राज्य और उन अन्य कार्यक्षेत्री जो पेशेवर पाठ्यक्रमों में प्रवेश सहित विभिन्न प्रकार के उद्धारण देने की शक्तियों से समर्पित हैं, उन्हें एक व्यक्ति की तरह स्वतंत्र नहीं माना जा सकता है या उन्हें इसके उपयोगकर्ता का चयन करने के लिए कोई निर्देशिका के साथ बिना किसी भी मार्गदर्शिका के उपहार करने का अनुमति नहीं हो सकता है। यदि प्रतिवेदन द्वारा यह पाया जाता है कि प्रतिष्ठान के कार्यों की क्रियावली विचारात्मक और आकारगरीय मानकों के आधार पर असमर्पित है और जिसके लिए अनुचित रूप से चयन किया जाता है, तो इस पर यह सुनिश्चित करने के लिए इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखा जाना चाहिए कि उचित राह पर है जिससे पीड़ित को उपयुक्त राहती है। हमारे संविधान तंत्र की मांग समानता और असमर्पितता और भेदभाव की अभाव को आवश्यकता है। कानूनी प्राधिकृतियों की क्रिया न्यायपूर्ण और संदेहमुक्त होनी चाहिए। विश्वविद्यालय को इससे मिलने वाली आचारधर्म और मानकों के साथ विचारण किया जा चाहिए और इसे इसे उन आचारधर्म और मानकों के साथ मेल खाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और जैसा कि एक निजी व्यक्ति, वैसे ही विचारण नहीं किया जा सकता है और इसकी क्रियाएँ ऐसी होनी चाहिए जो जाँच के बाद विचारण न किए जाने पर असमर्पित, अराजक या अनुचित साबित होती हैं। माइग्रेशन के माध्यम से प्रवेश अगर सही दिशा में नहीं हुआ है या यह कृत्रिम रूप से हुआ है तो इसे निरस्त किया जाना चाहिए। समानता का अधिकार हमारे संविधान तंत्र का हृदय और आत्मा है। समानता की गारंटी को एक व्यक्ति के अधिकार की पूरी श्रेणी माना गया है और इसे केवल तब लागू किया जाता है जब एक व्यक्ति को उसके अधिकार का प्रयोग करने या उसको दंड लगाने के मामले में ही नहीं बल्कि उपहार प्रदान करने के मामले में भी भेदभाव किया जाता है।

प्रारंभिक दृष्टिकोण से ही, यह यहाँ तक कि निजी प्रतिद्वंदियों के प्रवेश को निरस्त करने के लिए प्रतिवादी द्वारा किए गए आरोपों में संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रयोजन को आकर्षित करेगा, जिसके अनुसार इस सुप्रीम कोर्ट को इस पर न्याय करने और निर्णय देने का अधिकार है। इस सुप्रीम कोर्ट और एप्लिकेंट-विश्वविद्यालय और निजी प्रवासित उम्मीदवारों के द्वारा उचितरित तकनीकी आपत्ति पर न्याय के लिए विचार का वाद नहीं है।

बी.डी.एस. पाठ्यक्रम के छात्रों का प्रवास महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कैलेंडर द्वारा नियंत्रित है, जिसमें यह उपलब्ध है: "एक उम्मीदवार का प्रवास, जिसका बी.डी.एस. डिग्री भारतीय डेंटल काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं किया गया है, को अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रवास के लिए आवेदन आवेदक द्वारा यह किया जाना चाहिए कि M.D.U., रोहतक के परिणाम की घोषणा की गई तिथि से तीन महीने के भीतर है। यदि अनुरोध तीन महीने के बाद प्राप्त होता है, तो भारतीय डेंटल काउंसिल की मंजूरी प्राप्त करें।

10. आवेदक : -

(a) अवश्य पास होना उत्तीर्ण :-

(i) प्रथम पेशेवर बीडीएस इंतिहान का अन्य विश्वविद्यालय,

(ii) मेडिकल प्रवेश परीक्षा या जहां मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है पूर्व चिकित्सा का इसका समकक्ष इंतिहान साथ पर कम से कम 50% निशान में सकल का विषयों का अंग्रेज़ी, रसायन विज्ञान (जैविक और अकार्बनिक), भौतिक विज्ञान और जीवविज्ञान।

(b) अवश्य संबंधित को राज्य का हरयाणा या को राज्य सरकार किसका उम्मीदवार हैं आरक्षित सीटों पर प्रवेश दिया जाता है, और उनके द्वारा मेडिकल कॉलेज में प्रवास के लिए सिफारिश की जाती है, चिकित्सकीय कॉलेज, रोहतक;

(c) उत्पादन करना ऐसे सभी प्रमाणपत्र और यथासम्भव सभी शुल्क का भुगतान करता है मांग की से प्राचार्य/निदेशक का कॉलेज। ए उम्मीदवार अवश्य पास होना वैध कारण के लिए प्रवास। प्रवास नही सकता होना दावा किया रूप में और विश्वविद्यालय द्वारा बिना कोई कारण बताए अस्वीकार किया जा सकता है। प्रवास होगा के विरुद्ध अनुमति दी

गई एक रिक्त सीट, यदि कोई हो, बाहर की में स्वीकृत शक्ति वर्षका प्रवेश'।

(d) प्रवासन छात्र अवश्य शामिल होना नया कॉलेज के 30 दिनों के भीतर प्रवासन की मंजूरी द्वारा विश्वविद्यालय। अन्यथा, उसका प्रवास इच्छा खुद ब खुद खड़ा होना रद्द जब तक अवधिके लिए पर्याप्त कारण, है विस्तारित द्वारा कुलपति।"

इसी प्रकार, एमबीबीएस पाठ्यक्रम में स्थानांतरण निम्नलिखित प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है पंचांग : -

"प्रवास को चिकित्सा कॉलेज, रोहतक. के अलावा कब अधिकार दिया गया द्वारा अकादमिक परिषद'। एक उम्मीदवार का प्रवास एक मेडिकल कॉलेज से किसका एमबीबीएस डिग्री पहचाना नहीं गया है से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नहीं होगी अनुमति है। आवेदन हेतु प्रवास होना चाहिए बनाया द्वारा आवेदक अंदर 3 महीने का घोषणा का महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय परिणाम।यदि अनुरोध प्राप्त होता है बाद तीन महीने, की मंजूरी भारतीय चिकित्सा परिषद होना प्राप्त किया। आवेदक।

(a) अवश्य पास होना उत्तीर्ण :-

(i) प्रथम पेशेवर एमबीबीएस इंतिहान का अन्य विश्वविद्यालय;

(ii) मेडिकल प्रवेश परीक्षा या जहां मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है विषयों के कुल योग में कम से कम 50% अंकों के साथ प्री-मेडिकल या इसके समकक्ष परीक्षा का अंग्रेजी, रसायन शास्त्र (जैविक और अकार्बनिक)। भौतिक विज्ञान और जीवविज्ञान;

(b) हरियाणा राज्य या राज्य सरकार से संबंधित होना चाहिए। जिन अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया है आरक्षित सीटें, और हैं अनुशंसित द्वारा उन्हें के लिए प्रवास को चिकित्सा कॉलेज, रोहतक;

(c) उत्पादन करना सभी ऐसा प्रमाणपत्र और वेतन सभी फीस जैसा मई होना मांग की द्वारा निदेशक-प्रिंसिपलका कॉलेज।

एक उम्मीदवार अवश्य पास होना वैध के कारण प्रवास। माइग्रेशन नहीं हो सकता होना दावा किया एक बात के तौर पर कासही है और प्राचार्य द्वारा बिना कोई कारण बताए अस्वीकार किया जा सकता है। प्रवास होगा अनुमत ख़िलाफ़ ए खाली सीट, अगर कोई भी, बाहर का स्वीकृत ताकत में वर्ष का प्रवेश।"

11. माइग्रेशन का लाभ पाने के लिए अभ्यर्थी को यह साबित करना होगा कि वह प्रथम वर्ष उत्तीर्ण है। पेशेवर बीडीएस इंतिहान से कुछ अन्य विश्वविद्यालय, है उत्तीर्ण चिकित्सा प्रवेश द्वार परीक्षा या जहां मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है, प्री-मेडिकल या इसके समकक्ष इंतिहान साथ कम से कम 50% निशान में सकल ऐसा आवेदक अवश्य संबंधित को राज्य का हरियाणा या उम्मीदवार ऐसी सरकार का जिसका उम्मीदवार हैं आरक्षित सीटों पर प्रवेश दिया गया और राज्य सरकार द्वारा संबद्ध मेडिकल/डेंटल कॉलेज में प्रवास के लिए इसकी अनुशंसा की जाती है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय. पात्रता की शर्तों को सिद्ध करने के बाद आवेदक को यह करना होगा उत्पादन करना उपयुक्त प्रमाणित करें और सौंपना वैध कारण के लिए प्रवास।

12. इस मुकदमे के किसी भी पक्ष ने महर्षि के प्रवासन की स्थिति को चुनौती नहीं दी है दयानंद विश्वविद्यालय, जैसा विख्यात इस के साथ साथ ऊपर।

13. यह भी विवादित नहीं है कि सभी उम्मीदवार चाहे याचिकाकर्ता या उत्तरदाताओं के पास है पारित किया प्रथम पेशेवर बीडीएस और एमबीबीएस परीक्षा के लिए उनका कॉलेज चाहे वे किसी भी हों तक हरियाणा राज्य और उन्होंने उनके आधार पर संबंधित प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत कर दिए हैं दावा किया प्रवास। यह है भी नहीं विवाद वह माइग्रेशन पास होना नहीं गया मंज़ूर किया गया पर आधार का कोई योग्यता विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की जाती है और दावा किया जाता है कि विश्वविद्यालय के पास इसे बनाने की पूर्ण शक्ति है चयन का कोई भी उम्मीदवार आवेदन के लिए प्रवास अगर वह वह पूरा करता है अन्य स्थितियाँ।

14. यह तर्क दिया गया है और हम सहमत हैं कि तत्काल मामले में प्रवासन प्रभावी और सार है

बीडीएस/एमबीबीएस पाठ्यक्रम में जोड़-तोड़ प्रवेश और ये प्रवेश इसके तहत प्राप्त किए गए हैं परिस्थितियाँ जो हैं नहीं मुक्त संदेह से. सही का अन्य समान रूप से स्थित पास होना नहीं गया प्रतिवादी-विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा उचित रूप से ध्यान दिया गया। अन्य अभ्यर्थियों की संख्या जो अन्यथा प्रवास के लिए पात्र थे, उन्हें तलाश का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है प्रवेश द्वारा प्रवास। में

उन्नी कृष्ण वी. के राज्य एपी, 1993(2) एससीटी 512 (एससी) : संयुक्त 1993(1) एस.सी 474 . सुप्रीम अदालत भरोसा ***बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम*** पर ***मिलन का भारत, 1984(2) एससीआर 67*** जिसमें यह माना गया कि सही जीवन के लिए गारंटी लेख द्वारा 21 लेता है शैक्षिक सुविधाओं में।" यह आयोजित किया गया वह सही को संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन के अधिकार में शिक्षा निहित थी और इसकी अनुमति थी । यह आयोजित किया गया वह "सही शिक्षा के प्रति व्यवहार किया गया है एक के रूप में पारलौकिक महत्व का में ज़िंदगी काएक व्यक्ति को हजारों वर्षों से न केवल इस देश में, बल्कि सर्वत्र मान्यता प्राप्त है दुनिया।" अदालत ने महसूस किया कि शिक्षा प्रदान किए बिना नागरिक, में निर्धारित उद्देश्य प्रस्तावना का संविधान नही सकता होना हासिल। सही का शिक्षा था विख्यात को पास होना घटित हुआ अनुच्छेद 41 , 45 में और 46 की संविधान। भरोसा रखा गया था '***ब्राउन बनाम*** पर ***तख़्ता का शिक्षा (98 वकीलों ईडी। 873)*** कहाँ यह था गया आयोजित : -

"आज, शिक्षा शायद राज्य और स्थानीय सरकारों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है... यह है में आवश्यक है प्रदर्शन हमारे अधिकांश बुनियादी जिम्मेदारियाँ, यहाँ तक कि सेवा भी में सशस्त्र बल।यह है अच्छाई की बहुत नींव नागरिकता. आज यह है प्रमुख साधन जागृति में बच्चा को सांस्कृतिक मूल्य, में तैयार कर रहे हैं उसे के लिए बाद में पेशेवर प्रशिक्षण, और में मदद कर रहा है उसेअपने वातावरण में सामान्य रूप से समायोजित होने के लिए। इन दिनों, यह संदिग्ध है कि कोई भी बच्चा यथोचित रूप से हो सकता है अपेक्षित को सफल होना में ज़िंदगी अगर वह है अस्वीकृत अवसर का एक शिक्षा।"

हालाँकि, न्यायालय उस चरम दृष्टिकोण से सहमत नहीं था जिसके लिए राज्य बाध्य था उपलब्ध करवाना पर्याप्त संख्या का चिकित्सा कॉलेज/इंजीनियरिंग कालेजों और अन्य शिक्षात्मक संस्थानहालाँकि इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य को नागरिकों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए सम्मान आज्ञा का लेख 45 कौन चाहिए होना बनाया ए वास्तविकता। संदर्भ था बनाया को 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और यह आयोजित किया गया, "हो जैसा कि यह हो सकता है, हम पकड़ो कि एक बच्चा (नागरिक) 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार है।" इसे यह अधिकार माना गया शिक्षा के बाद बच्चे (नागरिक) को पूरा करता है आयु 14 वर्ष का विषय है तक की सीमा राज्य की आर्थिक क्षमता एवं विकास। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था में प्रवेश अभियांत्रिकी जो कॉलेज थे निजी द्वारा चलाएँ शैक्षणिक संस्थान और आयोजित वह वे थे पूरक में कार्य प्रदर्शन किया द्वारा राज्य। प्राणी संतुष्ट वह प्रवेश को निजी शिक्षात्मक संस्थान था नहीं प्राणी संचालित में अनुसार साथ कानून के प्रावधानों और संविधान के जनादेश के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने एक योजना प्रदान की विचार का को दूर विवेक में प्रबंध कुल मिलाकर में मामला का प्रवेश. जबकि इन्तेर्प्रेतिंग अवधि 'उपयुक्त अधिकार' सुप्रीम अदालत निपटा साथ यह को अर्थ सरकार, विश्वविद्यालय या अन्य प्राधिकारी जो () स्थापित करने की अनुमति देने में सक्षम था किसी प्रोफेशनल कॉलेज को मान्यता प्रदान करना। उन्नी कृष्णन में निर्धारित कानून की स्थिति को देखते हुए मामला (सुप्रा), यह नही सकता होना कहा वह विश्वविद्यालय कर सकना अनुदान दाखिले द्वारा प्रवास पर इसका मिठाई इच्छाऔर बिना अगले प्रक्रिया मुक्त संदेह और संशय से. ऐसी प्रक्रिया, नीति या नियम है आवश्यक को होना परीक्षण पर टच स्टोन का समानता और निष्पक्षता, अगर दाखिले हैं मिलाको होना नहीं आधारित ऊपर फेयरनेस या हैं परिणाम का भेदभाव, वही हैं उत्तरदायी को होना रद्द कर दिया गया.

15. यह है नहीं गया लाया को हमारा सूचना वह सीटें गिर रहा है खाली कौन थे अभिप्रेत को होना भरा हुआ

ऊपर प्रवास द्वारा थे कभी विज्ञापित afiording को अवसर योग्य संपर्क करने के लिए विश्वविद्यालयविशिष्ट परिस्थितियों में प्रवास के प्रयोजनों के लिए। समानता का अधिकार हासिल नहीं किया जा सकता जब तक समान स्थिति वाले सभी लोगों को अवसर न दिया जाए । सभी को अवसर देने से इनकार किया जा सकता है के लिए आधार रद्द करने सबका पलायन. हालाँकि, में तुरंत मामला कोई नहीं शिकायत की है के बारे में यह फूल है क्योंकि प्रवेश की अनुमति के लिए विश्वविद्यालय में आवेदन किया है और संपर्क किया है प्रवास।

16. क्रम में जाहिर करना वह चयन निष्पक्ष, उचित था और नहीं यह भेदभावपूर्ण है के लिए अनिवार्य था उत्तरदाता - विश्वविद्यालय को संतुष्ट अदालत के बारे में परीक्षण लागू या प्रक्रिया अपनायाको हटाना आशंका का भेदभाव। कुछ नहीं है गया लाया पहले हम के लिए हमारा अध्ययन।यह है सत्य वह उपयुक्त नियम/क़ानून करता है नहीं परिकल्पना करना वह योग्यता है अकेला मानदंड के लिए प्रवासन लेकिन इससे विश्वविद्यालय यह दिखाने की अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाता कि आदेश थे निर्धारित मापदण्ड एवं एकरूपता के आधार पर निष्पक्ष, निष्पक्ष एवं समान रूप से पारित किया गया प्रक्रिया अपनाया।

17. बीडीएस कोर्स में माइग्रेशन के मामले में भी गठित समिति की सिफारिशें इस उद्देश्य के लिए पालन नहीं किया गया और बिना कोई कारण बताए पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। की कार्रवाई उत्तरदाताओं में अनुमति प्रवास और स्वीकार छात्र को 2 वर्ष पेशेवर एमबीबीएस / बीडीएस कोर्स संदेह से मुक्त नहीं है। यहाँ तक कि समानता का अधिकार भी सिद्ध हो चुका है उल्लंघन के लिए कारण विख्यात इस के साथ साथ ऊपर। प्रवास का निजी उत्तरदाताओं प्राणी में उल्लंघन का मौलिक अधिकार है, इसलिए, उत्तरदायी को होना रद्द कर दिया गया.

18. विश्वविद्यालय कैलेंडर के तहत निर्धारित शर्तों में से एक यह है कि प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होने के अलावा आवेदक को दूसरे विश्वविद्यालय से प्रोफेशनल एमबीबीएस परीक्षा मेडिकल उत्तीर्ण होना चाहिए प्रवेश द्वार इंतिहान या कहाँ चिकित्सा प्रवेश द्वार इंतिहान है नहीं आयोजित पूर्व चिकित्सा या इसका अंग्रेजी विषयों के कुल योग में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ समकक्ष परीक्षा, रसायन विज्ञान (कार्बनिक और अकार्बनिक), भौतिकी और जीव विज्ञान। मौजूदा मामले में न तो याचिकाकर्ता और न ही निजी उत्तरदाताओं को या तो मेडिकल प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण दिखाया गया है राज्य में कौन वे थे पहले स्वीकार किया या में राज्य कहाँ प्रवास है ढूँढा गया के लिए। यह है भीनहीं पर रिकार्ड करें कि क्या मेडिकल प्रवेश परीक्षा कहाँ आयोजित किया गया था निजी उत्तरदाताओंथा प्राप्त दाखिले पहले उनका प्रवास। समान है मामला का याचिकाकर्ताओं चाह रहा है प्रवासतक अपील करनेवाला विश्वविद्यालय। गुजरने की अवस्था मेडिकल प्रवेश परीक्षा बहुत बढ़िया है महत्त्व और नही सकता होना अवहेलना करना पर खाता का जान-बूझकर मौन का व्यक्तियों चाह रहा है की ओर पलायन अपील करनेवाला विश्वविद्यालय। उद्देश्य का पूर्वोक्त शर्त देखने की है वह मेधावी छात्रों को एमबीबीएस / बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है और केवल ऐसे छात्रों को ही प्रवेश दिया जाता है चले गए के लिए के दौर से गुजर आराम का अवधि में एमबीबीएस नहीं व्यक्ति कर सकना होना अनुमति है को लोटनाबाहर का यह स्थिति कौन है गया इनकॉरपोरेटेड में कैलेंडर साथ आला दर्जे का वस्तु का केवल ऐसे अभ्यर्थियों को माइग्रेशन प्रदान करना जो पात्र होते हुए भी उसमें समायोजित नहीं किए जा सके सीटों की कमी या अन्य विभिन्न कारणों से बताएं। ऐसे व्यक्ति जो प्रवास चाहते हैं उनकी योग्यता के बावजूद, उन्हें कम से कम मेडिकल प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। केवल ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मेडिकल प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है न्यूनतम प्रतिशत अंकों के लेकिन थे असमर्थ विभिन्न विचारों के आधार पर प्रवेश पाने के लिए उस राज्य में, और राज्य के बाहर अन्य चिकित्सा संस्थान द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त में भर्ती कराया गया था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अकेले ही उस विशेष राज्य में प्रवास की मांग कर सकती है जहां मेडिकल प्रवेश है इंतिहान है ए स्थिति मिसाल के लिए चाह रहा है प्रवेश को पेशेवर अवधि। कोई अन्य व्याख्या चाहेंगे हराना बहुत उद्देश्य ढूँढा गया को होना हासिल द्वारा पूर्वोक्त स्थिति निर्धारित अंतर्गत विश्वविद्यालय कैलेंडर. एक व्यक्ति जिसके पास दिखाया गया है नहीं योग्य प्राप्त करके प्रवेश परीक्षा में अपेक्षित अंक उसकी अक्षमता के लिए पुरस्कृत नहीं किए जा सकते कम योग्यता द्वारा देने उसे प्रवेश द्वारा रास्ता का प्रवास। यह है नहीं विवादित वह में राज्य कहाँ

अपीलकर्ता - विश्वविद्यालय एक मेडिकल प्रवेश द्वार स्थित है परीक्षा हुई और सब के दावेदार सीट द्वारा प्रवास हैं नहीं दिखाया को पास होना प्रकट/योग्य कहा चिकित्सा प्रवेश द्वार इंतिहान में वह राज्य। अगर कोई नहीं का उन्हें है दिखाई दिया या योग्य द्वारा प्राप्त न्यूनतम अपेक्षित अंकों के बावजूद, उसे माइग्रेशन द्वारा प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। मान रहे हैं लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे हैं उपस्थिति में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नहीं थी आवश्यक या परीक्षा नहीं था आयोजित में राज्य, दावेदारों थे आवश्यक को दिखाओ वह वे था उत्तीर्ण पूर्व चिकित्सा या समकक्ष अंग्रेजी, रसायन विज्ञान (ऑर्गेनिक और) विषयों में कुल मिलाकर पचास प्रतिशत अंकों के साथ परीक्षा अकार्बनिक), भौतिकी और जीव विज्ञान। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि यह स्थिति थी या का अनुपालन किया गया नहीं। संदर्भ में विश्वविद्यालय कैलेंडर वह उम्मीदवार चाह रहे हैं प्रवास थे आवश्यक सदस्य बनने के लिए तक राज्य हरियाणा के ही संकेत मिलते हैं वह संदर्भ तक चिकित्सा प्रवेश परीक्षा उस राज्य में आयोजित ऐसी परीक्षा के संबंध में है। अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय था आवश्यक को विचार करना यह पहलू जबकि की अनुमति प्रवास और अनुमति निजी उत्तरदाताओं एमबीबीएस/बीडीएस की द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा में प्रवेश के लिए यह शर्त नहीं रखी गई है पूर्ण, आदेश कि रद्द में रिट याचिका देने प्रवेश द्वारा प्रवास में एमबीबीएस / बीडीएस अवधि को निजी उत्तरदाताओं है उत्तरदायी को होना रद्द कर दिया गया.

19. बाद भरोसा ऊपर प्रलय का यह अदालत में ***मीनाक्षी सिंगला वी राज्य का पंजाब और अन्य, 1991(2) एससीटी 720 (पी एंड एच) : 1991(4) एससीआर 87*** और ***राजीव पुरी वी पंजाब विश्वविद्यालय & अन्य. 1992(1) एससीटी 148(पी एंड एच) : 1992(1) आरएसजे 47*** और का सुप्रीम अदालत ***के हलीद*** में ***हुसैन वी तमिलनाडु सरकार के आयुक्त एवं सचिव एवं अन्य / _ 1987(4) एसएलआर 598,*** विद्वान एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चयन शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर किया गया होगा उम्मीदवार। रिट याचिका को स्वीकार करते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने इसे रद्द न करने का निर्णय लिया प्रवासन लेकिन इसके बजाय उत्तरदाताओं को निर्देश दिया गया कि वे रिट याचिकाकर्ताओं के प्रवासन की अनुमति दें अधिक सीटें. इसका निर्देशन किया गया। "दिए गए निर्देशों के मद्देनजर यदि कोई अतिरिक्त सीटें होनी हैं याचिकाकर्ता को समायोजित करने के लिए बनाया गया, इसे विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा सिविल में बनाया जा सकता है 1993 की रिट याचिका संख्या 13507। हालाँकि, 1993 की सीडब्ल्यूपी संख्या 13971 का निर्णय करते समय, विद्वान एकल न्यायाधीश ने सृजित की जाने वाली अतिरिक्त सीटों की संख्या आठ तक सीमित कर दी और अपीलकर्ता को निर्देश दिया- विश्वविद्यालय बीडीएस प्रथम वर्ष में उनकी योग्यता के आधार पर याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करेगा परीक्षा और केवल पांच और छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा यानी डेंटल कॉलेज, रोहतक में 3 और डीएवी में 2 शताब्दी, यमुनानगर। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे कहा कि एक मुनीश मदान को अनुमति दी गई थी एक कॉलेज से प्रवास पर यमुनानगर रोहतक में जो एक इंटर -कॉलेज था स्थानांतरण और अधीन अलग-अलग द्वारा विनियम. मुनीष मदान का प्रवास था चुनौती दी गई मुख्यतः पर मैदान कि अपीलार्थी-विश्वविद्यालय के कुलपति ने नियम-निर्देशों की परवाह किये बिना प्रवासन और के लिए निर्धारित अवधि जिसके भीतर अनुप्रयोग हो सकते हैं प्रस्तुत आदेश दिया था निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले इस प्रतिवादी का प्रवासन हुआ और उसे इसमें शामिल किया गया चिकित्सकीय कॉलेज, रोहतक पर 14.9.1993 में का अनुसरण प्रवास आदेश देना।

20. विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय इस सीमा तक प्रवासन को विरुद्ध मानता है प्रावधानों का कानून है ऊपर आयोजित यद्यपि के लिए अलग कारण जैसा विख्यात इस के साथ साथ ऊपर। तथापि, प्रवेश हेतु निर्देश दिया गया रिट याचिकाकर्ता बनाकर अधिक सीटें नहीं हो सकतीं होना यथासम्भव बरकरार रखा गया न्यायालय को ऐसे व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त सीटों के निर्माण का निर्देश देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है जो पास आता है अदालत रिट के माध्यम से याचिकाएँ. वहाँ की संभावना प्राणी अधिक सराहनीय चाहने के इच्छुक उम्मीदवार प्रवासन नहीं हो सकता होना से इंकार। पक्ष में की गई अवैधता का कुछ विशेषाधिकार प्राप्त उम्मीदवारों को उन लोगों के लिए दोहराए जाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है जो इसके लिए अदालत में आते हैं चाह रहा है ए समान इलाज। निर्माण का अतिरिक्त सीटें में पेशेवर कॉलेज ज़रूरत होना आवेदनके मन की शैक्षिक प्राधिकारियों को जिनकी आवश्यकता हो सकती है अतिरिक्त उपकरण और स्टाफ़ के लिए प्रदान शिक्षा में फ़ील्ड. बिना जानने या पता लगाने एकदम सही पद का स्टाफ़ और अन्य मांग के लिए सुविधाएं के दौर से गुजर बेशक, जारी करने, निर्गमन अतिरिक्त सीटों के सृजन के निर्देश मई नहीं केवल प्रतिकूल प्रभाव संस्थान लेकिन है भी हानिकारक को रूचियाँ का वे कौन हैं

निर्देशित को होना प्रदान किया अतिरिक्त सीटें. सुप्रीम अदालत में ***घर*** में ***सचिव, केन्द्र शासित प्रदेशों का चंडीगढ़ बनाम दर्शजीत सिंह ग्रेवाल और अन्य, 1993(4) एससीटी 415 (एससी) : 1993(4) एसएलआर 556*** , सम को अस्वीकृत कर दिया अभ्यास देने का द्वारा प्रवेश उच्च न्यायालय सिवाय अंतरिम आदेशों के में दुर्लभ मामले जहां इस तरह के आदेश को पारित न करने से गंभीर चोट लगने की संभावना थी, जो नहीं हो सकती थी मरम्मत बाद में।

21.जिस प्रकार से योग्य न्यायाधीश के न्यायाधीश ने न्याय हुआ है कि प्रवास विधि के खिलाफ है, उसे उचित रूप से बनाए रखा जाता है हालांकि इसके लिए उपरोक्त रीति अलग है। हालांकि, यह नहीं उपजा सकता कि ऐसे व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त सीटें बनाने के लिए न्यायालय को मार्गदर्शन करने का कोई प्राधिकृतिक नहीं है जो याचिका पत्रों के रूप में न्यायालय के पास आते हैं। इसका संभावना है कि वांछनीय प्रवास की ओर बढ़ने वाले और भी योग्य उम्मीदवार हो सकते हैं। जो विशेषाधिकृत उम्मीदवारों के लाभ में की गई गलती को उन लोगों के लिए बार-बार करने के लिए कोई मुकदमा हो सकता है जो एक समान प्रवद्र्धन की तलाश में न्यायालय की ओर से आते हैं। पेशेवर कॉलेज में अतिरिक्त सीटें बनाने के लिए शिक्षा अधिकारियों के मन का अनुप्रयोग की आवश्यकता है जो शिक्षा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त यंत्र और कर्मचारी की स्थिति को नहीं जानकर या निर्धारित करके बिना, अतिरिक्त सीटें बनाने के निर्देश जारी किए जाने पर संस्थान को हानि पहुंच सकती है और जिनको अतिरिक्त सीटें प्रदान की जाने की दिशा में यह हानिकारक हो सकता है। उच्चतम न्यायालय ने 'होम सेक्रेटरी, यू.टी. ऑफ चंडीगढ़ बनाम दर्शजीत सिंह ग्रेवाल और अन्य, 1993(4) SCT 415 (SC): 1993(4) S.L.R. 556' में यह भी निन्दा की कि अतिरिक्त सीटें बनाने की प्रथा को उच्च न्यायालय द्वारा प्रवेश देने की केवल अवसान याचिकाओं के माध्यम से केवल विशेष प्रकार की मामूली मामूली स्थिति को छोड़कर हमेशा के लिए हानि का कारण बन सकता है।

22. विद्वान वकील उपस्थित हो रहे हैं के लिए जो उम्मीदवार पाने में कामयाब रहे प्रवासन द्वारा प्रवेश तर्क दिया है कि भले ही रिट याचिकाएं स्वीकार कर ली जाती हैं और प्रवासन को कानूनी नहीं माना जाता है आदेश आक्षेप नहीं करना चाहिए होना ऐसे ही रद्द कर दिया गया नतीजा होगा एक महान में को कठिनाई जो छात्र प्रवास के बाद नये संस्थान से जुड़े हैं। सर्वोच्च के निर्णय पर भरोसा किया जाता है दर्शजीत सिंह के मामले में न्यायालय (सुप्रा) और इस न्यायालय की सिविल रिट याचिका संख्या 1745 1992 में ' ***थापर संस्था का अभियांत्रिकी और तकनीकी, पटियाला वी राज्य का पंजाब, 1995(2) एससीटी 26 (पी एंड एच) (डीबी) ने 2.9.1994 को निर्णय लिया।*** हम इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं और इसकी अनुमति नहीं दे सकते अवैधता को होना कायम रखा या सफल उम्मीदवार प्राणी प्रदत्त साथ कोई अनावश्यक के लिए लाभ उनके में कृपादृष्टि। एक बार यह आयोजित किया जाता है वह माइग्रेशन प्राप्त कर लिया गया है अवैध तरीकों से और हिंसा मेंन केवल कानून के प्रावधान बल्कि संविधान के भी प्रावधानों के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाई जा सकती कौन पास होना प्राप्त किया ऐसा अनावश्यक के लिए लाभ में उनका कृपादृष्टि। में तुरंत मामला, सफल अभ्यर्थियों को मिला खुली आँखों से माइग्रेशन द्वारा बीडीएस में प्रवेश और परिणाम के बारे में उनका भाग्य दीवार पर स्पष्ट रूप से लिखा है, इसलिए जोड़-तोड़ वाले दाखिले जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती विशेष रूप से कब कार्रवाई का उत्तरदाताओं देने प्रवास ख़बरदार आदेश दिनांकित 19.10.1993 (अनुलग्नक पी-4) अभी तक बीडीएस कोर्स के रूप में संबद्ध है चुनौती दी गई में अदालत दिनों के अंदर उसके बाद. जिन उम्मीदवारों के पास है पाने में सफल रहे प्रवास थे नहीं जारी रखने की अनुमति दी गई द्वाराकोई विशिष्ट आदेश का अदालत। समान है मामला का उत्तरदाताओं कौन पास होना गया चले गए में

एमबीबीएस अवधि। भरोसा का वकील के लिए उत्तरदाता पर दर्शजीत सिंह का मामला (सुप्रा) है उस स्थिति में उत्तरदाताओं को न्यायालय के आदेशों द्वारा प्रवेश प्रदान किया गया था यह साबित कर दिया गया है कि अभ्यर्थी एक से अधिक समय से संस्थान में पढ़ रहे हैं वर्ष। सुप्रीम अदालत देखा, "हम हैं विवश को जोड़ना वह यह चाहेंगे पास होना गया अधिक उपयुक्त यदि उच्च न्यायालय था नहीं निर्देशित उत्तरदाताओं होना स्वीकार किया में चंडीगढ़ अंतरिम आदेशों के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेज..." आगे कहा गया, "...भले ही रिट याचिका विफल रहता है, अंतरिम आदेश की शरारत नही सकता होना को ध्यान में रखते हुए सुधार किया गया परिवर्तन स्थिति में, के साथ युग्मित व्यतीत समय की। यह बिल्कुल स्थिति का सामना करना पड़ रहा है हम।" ऐसा नहीं है स्थिति में मामला पहले हम।

23. इस महकमे के विभाजन बेंच ने 'थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी' के मामले में भी प्रमुखतः उस स्थिति के आधार पर प्रमुखतः यह साबित नहीं किया कि प्रभावित छात्रों को न्यायाधीशों के आदेश के कारण प्रवेश प्रदान किया गया होने के बावजूद भी चयन को रद्द किया जाए। उस मामले में, महकमा ने यह दिशा दी, "हालांकि, इस पर ध्यान दिया जाता है कि उन छात्रों को जिन्हें न्यायाधीशों के आदेशों के आधार पर प्रवेश दिया गया था, को उनके अध्ययन को जारी रखने की अनुमति दी जाएगी और उनका प्रवेश नियमित किया जाएगा।" इस संदर्भ में कोई प्रवासित छात्र न्यायाधीशों के आदेश के आधार पर अध्ययन जारी रखने की अनुमति नहीं मिली है।

24. इस परिस्थितियों के तहत, लेटर्स पेटेंट एपील संख्या 78, 79, 80, 211 और 212/1994 को आंशिक रूप से स्वीकृत किया जाता है। ज्ञानी एकल न्यायाधीश के आदेश को इतना कि वह उसके सामने लिखे वृद्धि सीटें बनाकर पेटीशनरों को प्रवेश प्रदान करने की दिशा में है, वह रद्द किया जाता है। ज्ञानी एकल न्यायाधीश के आदेश और प्रवास के आदेश को जिसके माध्यम से मिसेज निताशा पॉल, मिसेज पुनीत, मिसेज बिंदु बंसल, श्री सुमित मलिक, मिसेज मोनिका भसीन, मिसेज पूजा बत्रा, श्री मनोज मित्तल, श्री तरुण कुमार भुतानी, श्री मुनिश मदान, मिसेज अंजुला गिरधर, मिसेज शाली, मिसेज राशी मजीथिया, मिसेज एरु अरोड़ा, पुनीत सदाना बी.डी.एस. कोर्स और मिसेज भवाना नरुला, श्री मनीष जैन, मिसेज अंजली हुड्डा और मिसेज अनामिका बिश्नोई एम.बी.बी.एस. कोर्स में प्रवेश प्रदान किया गया था, उसे रद्द किया जाता है। ऐसे प्रतिस्पर्धियों द्वारा रखी गई सीटें खाली घोषित की जाती हैं। उत्तरदाता विश्वविद्यालय को रिक्तियों का विज्ञापन करने और इच्छुक छात्रों से आवेदन प्राप्त करने के बाद, विश्वविद्यालय कैलेंडर के अनुसार एक उचित और समरूप नीति और मानकों का अनुसरण करके चयन करने के लिए निर्देशित किया जाता है। छात्रों के प्रवास के उद्देश्यों के लिए चयन करने के लिए छात्रों की प्रतिष्ठा को एक शर्त के रूप में रखा जाएगा। सिविल पेटीशन संख्या 8097, 8215, 8589, 9620, 7991, 8007/1994 और 16067/1993 भी उपर्युक्त सीमा तक स्वीकृत हो जाएंगे।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मिताली अग्रवाल

सिद्धांत रॉयल

रीतिका शर्मा

उदित अग्रवाल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

हरियाणा